भारत सरकार
कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय
कृषि एवं किसान कल्याण विभाग
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं.389
04 फरवरी, 2025 को उत्तरार्थ

विषयः- कृषि क्षेत्र में स्टार्टअप

389. श्रीमती भारती पारधीः
श्री श्रीरंग आप्पा चंदू बारणेः

क्या कृषि और किसान कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या कृषि क्षेत्र में स्टार्टअप द्वारा विकसित नई/नवीन प्रौद्योगिकियां कृषि को वहनीय और जलवायु अनुकूल बनाने में योगदान करती हैं;

(ख) यदि हां, तो क्या कृषि स्टार्टअप प्रौद्योगिकी को विस्तार के माध्यम से किसानों के साथ इन्हें जोड़ना उसकी पहुंच और अंगीकरण की दृष्टि से महत्वपूर्ण है;

(ग) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है;

(घ) क्या सरकार ने कृषि विस्तार प्रणाली को सुदृढ़ करने के लिए "विस्तार" नामक प्रायोगिक परियोजना शुरू की है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) देश में कृषि और कृषि क्षेत्रों से जुड़े मौजूदा स्टार्टअप्स की विशेषकर बालाघाट, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र सहित संख्या का राज्यवार ब्यौरा क्या है?

उत्तर

कृषि एवं किसान कल्याण राज्य मंत्री (श्री राम नाथ ठाकुर)

(क) से (ग): राष्ट्रीय कृषि विकास योजना (आरकेवीवाई) के अंतर्गत "नवाचार और कृषि-उद्यमिता विकास" कार्यक्रम स्टार्टअप को बढ़ावा देने के लिए वित्तीय और तकनीकी सहायता प्रदान करके नवाचार और कृषि-उद्यमिता को बढ़ावा देता है। 05 नॉलेज पार्टनर्स (केपी) और 24 आरकेवीवाई एग्रीबिजनेस इनक्यूबेटर (आर-एबीआई) इस कार्यक्रम के कार्यान्वयन के लिए प्रशिक्षण प्रदान करते हैं और स्टार्टअप को इनक्यूबेट करते हैं।

स्टार्टअप द्वारा विकसित नई और नवोन्मेषी तकनीकें कृषि को सतत और जलवायु के अनुकूल बनाने में योगदान देती हैं। कृषि क्षेत्र में काम करने वाले स्टार्टअप जैसे कि सतत कृषि, कृषि-जैव प्रौद्योगिकी, कृषि मशीनीकरण, वेस्ट-टू-वेल्थ सोल्युशंस आदि कीटनाशकों, उर्वरकों और सिंचाई के अत्यधिक उपयोग को नियंत्रित करने में मदद कर रहे हैं। ये समाधान संसाधन दक्षता को बढ़ाते हैं, ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन को कम करते हैं, और सटीक सिंचाई, जैविक इनपुट और नवीकरणीय ऊर्जा अपनाने के माध्यम से जलवायु-अनुकूल खेती को बढ़ावा देते हैं। उल्लेखनीय नवाचारों में जैव-फ़िल्टर-आधारित अपशिष्ट जल उपचार, केले के तने से वीगन लेदर, और कार्बन पृथक्करण एवं व्यापार के लिए डिजिटल प्लेटफ़ॉर्म आदि शामिल हैं।

विस्तार सेवाओं के माध्यम से कृषि स्टार्टअप तकनीक को किसानों से जोड़ना, नवीन समाधानों की व्यापक पहुँच और अपनाने को सुनिश्चित करने के लिए महत्वपूर्ण है। कृषि विस्तार सेवाएँ ऑन-ग्राउंड प्रदर्शन, प्रशिक्षण कार्यक्रम, डिजिटल एडवाइजरी प्लेटफ़ॉर्म और किसान मीट-अप प्रदान करके इस अंतर को कम करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। इनक्यूबेटर के माध्यम से विस्तार, कृषि विज्ञान केंद्रों, एफ़.पी.ओ. और ग्रामीण नेटवर्क के साथ जुड़े स्टार्टअप तकनीक और क्षमता निर्माण को बढ़ावा देते हैं। इस संपर्क को मजबूत

करने से नवाचारों को अपनाने में तेजी आती है, किसानों की आय में सुधार होता है और जलवायु-अनुकूल और सतत कृषि का समर्थन होता है।°

(घ): विस्तार (वर्चुअली इंटीग्रेटेड सिस्टम टू एक्सेस एग्रीकल्चरल रिसोर्सेस) का उद्देश्य विभिन्न प्लेटफ़ॉर्म पर विश्वसनीय, मान्य और अद्यतित संसाधनों को एकीकृत करके कृषि के लिए एक एकीकृत डिजिटल इकोसिस्टम विकसित करना है। यह केंद्र-राज्य अभिसरण को अपनाकर, स्टेकहोल्डर्स के साथ साझेदारी को बढ़ावा देकर और आई.सी.ए.आर. संस्थानों और राज्य कृषि विश्वविद्यालयों के व्यापक प्रयासों के साथ तालमेल बिठाकर किसानों के फीडबैक को शामिल करने के लिए दो-तरफ़ा संचार को सक्षम करते हुए डिजिटल समाधानों की स्केलेबिलिटी, एक्सेसबिलिटी और इनक्लूसिविटी को बढ़ाने पर ध्यान केंद्रित करता है।

(ङ): वर्ष 2019-20 से 2024-25 के दौरान, पीएम-आरकेवीवाई के "नवाचार एवं कृषि-उद्यमिता विकास" कार्यक्रम के अंतर्गत विभिन्न केपी और आर-एबीआई के माध्यम से 1749 कृषि स्टार्टअप को 124.96 करोड़ रुपये की वित्तीय सहायता जारी की गई है। कार्यक्रम के अंतर्गत कृषि क्षेत्र से जुड़े मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र सहित स्टार्टअप की संख्या का राज्य-वार विवरण अनुबंध पर दिया गया है। मध्य प्रदेश के बालाघाट में एक स्टार्टअप है।

अनुबंध

पीएम-आरकेवीवाई के "नवाचार और कृषि-उद्यमिता विकास" के अंतर्गत केपी और आर-एबीआई द्वारा वर्ष 2019-20 से 2024-25 के दौरान समर्थित मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र सहित देश में राज्य/केंद्र शासित प्रदेश-वार कृषि स्टार्ट-अप का विवरण निम्नलिखित है:

क्र. सं.	**राज्य**	**स्टार्टअप्स की कुल संख्या**
1	आंध्र प्रदेश	62
2	अरुणाचल प्रदेश	13
3	असम	50
4	बिहार	49
5	छत्तीसगढ़	80
6	गोवा	3
7	गुजरात	49
8	हरियाणा	87
9	हिमाचल प्रदेश	34
10	जम्मू एवं कश्मीर	24
11	झारखंड	7
12	कर्नाटक	211
13	केरल	99
14	मध्य प्रदेश	69
15	महाराष्ट्र	231
16	मणिपुर	22
17	मेघालय	2
18	मिजोरम	25
19	नागालैंड	2
20	ओडिशा	62
21	पंजाब	52
22	राजस्थान	71
23	तमिलनाडु	143
24	तेलंगाना	99
25	त्रिपुरा	13
26	उत्तर प्रदेश	88
27	उत्तराखंड	33
28	पश्चिम बंगाल	22
29	दिल्ली एनसीआर	42
30	अंडमान और निकोबार	1
31	चंडीगढ़	3
32	पांडिचेरी	1
कुल		**1749**

*****